भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1233

11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

सेल द्वारा निवेश

1233. श्रीमती डी.के. अरुणा:

श्री इटेला राजेंदर:

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अगले कुछ वर्षों में अपनी 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश योजना के हिस्से के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिए 6,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी;

(ख) क्या सेल और इस्पात उद्योग ने चीन द्वारा भारत में सस्ती धातु की डंपिंग को नियंत्रित करने के उपायों के लिए सरकार से संपर्क किया है और भविष्य में इस खतरे से निपटने के ले कदम उठाए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में नए इस्पात संयंत्र की स्थापना में ही प्रगति और आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और तेलंगाना में वीएसपी को अन्य वित्तीय सहायता के साथ-साथ खामियों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए सेल के लिए क्रमश: 5,700 करोड़ रुपए तथा 7,500 करोड़ रुपए के पूंजीगत (कैपेक्स) व्यय को मंजूरी दी गई है। पूंजीगत व्यय में समाप्त हो चुकी योजनाओं के लिए माइलस्टोन भुगतान, जारी योजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान, पूंजीगत सुधार/ स्पेयर और संयुक्त उद्यमों में पूंजीगत व्यय में सेल का हिस्सा शामिल है।

(ख): इस्पात उद्योग ने फ्लैट इस्पात उत्पादों, सीआरएनओ और हॉट रोल्ड कॉइल्स के आयात पर नामित प्राधिकरण के समक्ष आयात से संबंधित जांच शुरु करने के लिए याचिका दायर की है।

जारी..

(ग): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर एक सुविधाकर्ता के रुप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्रों की स्थापना के संबंध में उद्योग द्वारा तकनीकी- वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स की सुगमता, बाजार तक पहुंच इत्यादि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

****